

मणिपुर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई

इंफाल
मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक प्रतिबंधित संगठन के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 11 हथियार तथा 10 आईईडी जब्त किए।
इस गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के दो उग्रवादियों को गुरवार को थौबल जिले के वांगजिंग खाबाखोंग इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से दो हथगोले जब्त किए गए। सुरक्षा बलों ने तेगनौपाल, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में तलाश अभियान के दौरान 11 हथियार और कई आईईडी जब्त किए। तेगनौपाल जिले से नौ एमएम की दो देसी पिस्तौल, मैगजीन, 10 आईईडी और आठ हथगोले जब्त किए गए।

वक्फ संपत्तियों का होगा उपयोग: धामी

देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा "गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा" संदेश के साथ वक्फ जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमांदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गोतम कहा कि वक्फ की जो भी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी, उन पर गरीब और मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे।

अमेरिका में आतंकी हैप्पी गिरफ्तार

चंडीगढ़
पंजाब के मोस्टवांटेड आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को भारत लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत जल्द ही हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को भारत लाया जाएगा। पासिया को अमेरिका में जांच एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया है। पासिया के आने के बाद पंजाब में कई ग्रेनेड हमलों की गुंथी सुलझ सकती है। एफबीआई की ओर से हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी का अधिकारिक ऐलान किए जाने के बाद शुक्रवार को पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्ता की।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी

हेराल्ड का नाम आते ही कांग्रेस परेशान हो जाती है: बीजेपी



नई दिल्ली
पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड घोटाला कांग्रेस के मॉडल ऑफ कर्रप्शन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को चंद नहीं, बल्कि विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। साथ ही सवाल उठाया कि आखिर ये विज्ञापन किस आधार पर दिए जाते हैं, जबकि अखबार नहीं छाप रहे हैं?
हेराल्ड का नाम आते ही कांग्रेस परेशान हो जाती है: बीजेपी
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहां कहा कि हेराल्ड का नाम सामने आते ही पार्टी के पूरे तंत्र में एक तरह की घबराहट, बेचैनी और असहजता दिखाई देने

लगती है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला अपने आप में एक ऐसा मॉडल है, जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है।
उन्होंने कहा कि कुछ अखबार केवल कागजी होते हैं, जो छपते, बिकते और पढ़े नहीं जाते और नेशनल हेराल्ड इसी श्रेणी में आता है।
कांग्रेस शासित राज्यों के अखबार को विज्ञापन देने को लेकर निशाना साधते हुए अनुराग ने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी पहले खटाखट मॉडल की बात करते थे। आज कांग्रेस शासित राज्यों में वही मॉडल खटाखा, बीमार और लाचार हो गया है। वहां की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड जैसे संस्थानों को विज्ञापन देकर सरकारी पैस दिए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट को 'सुपर संसद' कहने पर छिड़ा घमासान

राष्ट्रपति-राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है: सिब्बल

नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को एक बयान दिया- जज राष्ट्रपति की सलाह न दें। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। सिब्बल ने कहा, 'भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति-राज्यपाल की सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ, दुखी भी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए।' सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा- 'लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा को सांसदी गवानी पड़ी थी। तब धनखड़ को यह मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ दो जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं।'
सिब्बल बोले- देश को न्यायपालिका पर भरोसा
सिब्बल ने कहा- आज के समय में अगर किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है, तो वह न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की ताकत से मिली है। ऐसे में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो



जज के घर नोटों का बंडल मिला, एफआईआर क्यों नहीं हुई: उपराष्ट्रपति

राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने 17 अप्रैल को कहा था कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी



मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की इन-हाउस

किसी आम आदमी के घर होता, तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होतीं। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने 17 अप्रैल को कहा था कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।

अपने अधिकार का प्रयोग कर रिव्यू डाल सकते हैं। वे अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह पूर्ण

दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की



नई दिल्ली
शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दाऊदी बोहरा समुदाय की राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर जारी करते हुए यह जानकारी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी। उन्होंने

वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह लंबे समय से लंबित मांग थी। प्रधानमंत्री ने वक्फ के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की और कहा कि इस अधिनियम को लाने के पीछे दिया और कहा कि यह लंबे समय से लंबित मांग थी। प्रधानमंत्री ने वक्फ के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को टेल्का के सीईओ एलन मस्क से फिर बात की। यह इस साल की दूसरी बातचीत है। दोनों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा, मैंने एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत में इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे।
भारत अमेरिका के साथ...



पीएम ने आगे कहा-हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि

पिछले दिनों ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।
भारत आ रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति
इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा अगले हफ्ते के शुरू में भारत की यात्रा पर आएंगे और इस दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। यह यात्रा ट्रंप प्रशासन के शुल्क विवाद के कारण बढ़ते वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच होगी। वेंस के कार्यालय ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा पर रहेंगे।

शरबत जिहाद पर रामदेव बोले- मैंने नाम नहीं लिया था

मथुरा
योग गुरु बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव किया। रामदेव ने कहा- मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। रूह अफजा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि, हमदर्द जैसी कंपनियों को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित हैं। और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश



होना चाहिए। यहां बात सनातनियों की है, उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी

वीडियो में रामदेव बाबा पतंजलि के शरबत का प्रचार करते दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं- गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जरूर है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है। जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे, तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे।

चिकित्सक की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना: मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक चिकित्सक की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है। यदि किसी डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से है। चिकित्सक की संवेदना गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकती है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों को यह नसीहत भी दी की वे बेवजह मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने की प्रवृत्ति से बचें और मरीज को क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने में रिस्क लेने की आदत डालें। सीएम योगी शुक्रवार दोपहर बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर के परिसर में



500 लोगों की क्षमता वाले विश्राम सदन (रैन बसेर) का भूमि पूजन-शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। 44.34 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह विश्राम सदन पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्राम सदन होगा। इसका निर्माण पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के

सीएसआर निधि से कराया जा रहा। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चिकित्सा संस्थान डॉक्टर के व्यवहार के माध्यम से संवेदना का केंद्र भी होता है। संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज भर्ती होने आता है तो उसके साथ कम से कम 3 या 4 अटेंडेंट होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई बार अटेंडेंट की

संख्या 10 तक हो जाती है। ऐसे में मरीज के साथ आने वाले अटेंडेंट को आश्रय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 500 बेड के विश्राम सदन को शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर एम्स को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स गोरखपुर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2016 में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला मैच एडमिशन लिया था और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एम्स का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने करीब डेढ़ वर्ष पहले लखनऊ में एसजीपीजीआई के अपने दौरे के दौरान सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों को देख उनकी व्यवस्था के लिए अटेंडेंट शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए थे। मन में आया कि एसजीपीजीआई,

केजीएमयू, बीएचयू में और एम्स गोरखपुर में पेशेंट अटेंडेंट के लिए कोई केंद्र बनने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी अवनीश अवस्थी को दी गई। उन्होंने प्रयास शुरू किए तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल के लिए तीन रैन बसेर दिए। पावर मिनिस्ट्री के सहयोग से एम्स गोरखपुर के लिए रैन बसेरा स्वीकृत हुआ।
याद दिलाया तीमारदारों के भोजन के लिए रियायती मॉडल
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 20 साल पहले इसेफेलाइटिस के पीक समय में शुरू किए गए तीमारदारों के भोजन के लिए रियायती मॉडल का भी उल्लेख किया।

चक्काण, साआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित समेत कई अधिकारी मौजूद थे। नक्सलियों के सरेंडर का वीडियो साझा किया है। आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुकमा में ऑपरेशन चलाया गया था।

शहर कार्बन एमिशन करेंगे, तो नेचर पाप धोने नहीं आएगा, हमें उठानी होगी जिम्मेदारी : भूपेंद्र यादव

एजेंसी **भोपाल।** केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पारंपरिक जीवनशैली, विशेषकर जनजातीय समाज की प्रकृति के साथ समरसता का आदर्श उदाहरण रही है। पहले विवाह जैसे अवसरों में पतल जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग होता था, लेकिन अब सभ्यता का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हर जगह कचरा ही कचरा है, चाहे गांव हो, ट्राइबल या नॉन-

ट्राइबल, हम सब प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि जो समुदाय जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में रहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना होगा। यह सिर्फ सरकार या एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है। यदि शहर कार्बन एमिशन करेंगे, तो नेचर कोई उनके पाप धोने नहीं आएगा। सभी को मिलकर सोचना और जिम्मेदारी निभानी होगी। वे राजधानी



बना दिए, सेंचुरी बना दी, अपने-अपने एरिया तय कर दिए। लेकिन जैसे ही ये एरिया तय हुए, सबसे पहले कहा गया, आबादियों को बाहर

करो। यही इस पूरे संकट की जड़ है। सरकार के नाते अगर फॉरेस्ट की बात करें, तो उसकी अपनी एक सीमा और भूमिका है। लेकिन जब हम उसे आजीविका से जोड़ने की बात करते हैं, तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। मैं खुद देखता हूँ कि हमारे जनजातीय समुदाय जिन क्षेत्रों में जंगल हैं, वहां जंगल के साथ जीने की सालों पुरानी परंपरा रही है। जब हम शासन के माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, तो यह विचार करना

जरूरी हो जाता है कि हम उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं या उनके कष्ट बढ़ा रहे हैं। आज यह साफ दिखता है कि कई बार हम उनके कष्ट ही बढ़ा रहे हैं।

वनांचल में पलायन की स्थिति बनी- कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उर्डे ने कहा आज का विषय बहुत संवेदनशील और अंतर चेतना से जुड़ा हुआ विषय है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सालों का हमारे जीवन से वनवासी समाज

छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सल दम्पति सहित 40 लाख के 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

एजेंसी **सुकमा।** छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के माड़ और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय एक नक्सल दम्पति सहित 22 नक्सलियों ने सीआरपीएफ डीआईजी और एसपी सुकमा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें दम्पति महिला के साथ आठ अन्य महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर शरा शासन ने कुल 40 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है। इन आत्मसमर्पित 01 पुरुष और 01 महिला नक्सली पर 08-08 लाख, 01 पुरुष और 01 महिला नक्सली पर 05-05 लाख, 02 पुरुष और 05 महिलाओं पर 02-02 लाख, 01 पुरुष नक्सल पर 50 हजार इस तरह से इन सभी 22 नक्सलियों पर कुल 40 लाख 50 हजार रुपये के इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाली नौ में से सात महिला नक्सलियों पर कुल 15 लाख रुपये का इनाम था। छत्तीसगढ़ शासन की 'छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति' और 'नक्सल मुक्त पंचावत' सुकमा पुलिस के चलाए जा रहे 'नियद नेछा नार' योजना से प्रभावित होने और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव के साथ नक्सलियों के अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 09 महिला सहित 22 नक्सलियों ने बिना हथियार नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का निर्णय लिया।

शादी समारोह में आए 5 युवक नहर में डूबे, 3 को बचाया, 2 का नहीं चला कुछ पता

बिजनौर। धामपुर से बिजनौर शादी समारोह में आए पांच युवक नहर में डूब गए, जिसमें से दो युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। यह हादसा थाना हटदौर के झालू नहर के पास हुआ। युवक लौटते वक्त नहर में नहाने के लिए रुके थे, और इसी दौरान पानी में डूबने लगे। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और जमीर आशिफ और ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि, आशिल और जोशान का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने खोजबीन तेज कर दी है। यह घटना इलाके में शोक का कारण बनी हुई है, और ग्रामीणों ने हादसे के बाद दुख और चिंता जताई है। स्थानीय अधिकारियों ने युवक के परिजनों से संपर्क किया है और खोज अभियान जारी रखा है।



‘करप्शन और कांग्रेस पर्यायवाची शब्द’, नेशनल हेराल्ड केस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव का तंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि इस मामले में ईडी द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जाना, घोटाले में पूरी तरह से उनकी सलिप्तता को दर्शाता है। सीएम विष्णु देव साय ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें यह मान लेना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे मामलों में बचाव की कोशिश कोर्ट में करना चाहिए, न कि सड़क पर। वैसे भी सबको यह पता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार अभी भी जमानत पर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'करप्शन और कांग्रेस, ये पर्यायवाची शब्द जैसे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में भी जिस तरह के संस्थागत घोटाले और धोखाधड़ी किए गए, उसका सच जनता के सामने आ चुका है। मामले में ईडी द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जाना, घोटाले में पूरी तरह से उनकी सलिप्तता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालने की कोशिश या इसके विरुद्ध सड़क पर आना यह साबित करता है कि कोर्ट में इनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है। कांग्रेस के यह पता है कि आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य पुख्ता है। सीएम विष्णु देव साय ने आगे लिखा, 'गांधी परिवार को अब यह मान लेना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे मामलों में बचाव की कोशिश कोर्ट में करना चाहिए, न कि सड़क पर। वैसे भी सबको यह पता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार अभी भी जमानत पर है। उन्हें कानूनी उपचार का सहारा लेना चाहिए। अनावश्यक प्रोपेगंडा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।' बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने है। दोनों दलों के बीच वार-पलटवार भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा, कांग्रेस को घेर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव ने मामले को लेकर कांग्रेस को फिर से घेरा।



श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अब यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया है।

एजेंसी **नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'श्रीमद्भगवद्गीता' और भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे प्रत्येक भारतीय के

लिए गर्व का क्षण बताया। दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए जानकारी दी कि 'गीता' और 'नाट्यशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के इसी पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया जाना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध



संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान किया जाना है। गीता और नाट्यशास्त्र

ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करना जारी रखे हुए है।' इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अब यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया है। यह वैश्विक सम्मान भारत की शाश्वत बुद्धिमत्ता और कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है।' उन्होंने

आगे लिखा, 'ये कालातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक हैं, ये दार्शनिक और सौंदर्यपरक आधार हैं, जिन्होंने भारत के विश्व-दृष्टिकोण और हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्ति के तरीके को आकार दिया है। इसके साथ ही, अब इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में हमारे देश के 14 अभिलेख शामिल हो गए हैं।' 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसका मकसद विश्वभर के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को

संरक्षित करना है। इसके साथ ही इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाना होता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुई थी। सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के सम्मान और संरक्षण के लिए हर साल 18 अप्रैल को 'विश्व धरोहर दिवस' मनाया जाता है। विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में यूनेस्को द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। विश्व धरोहर सम्मेलन को दुनिया भर के देशों ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को सुरक्षा के लिए अपनाया था।

नेशनल हेराल्ड मामला: अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

‘कांग्रेस शासित राज्य जनता के टैक्स के पैसे से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के रूप में धन दे रहे हैं’

एजेंस **नई दिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसे कांग्रेस का 'भ्रष्टाचार मॉडल' करार दिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर यंग इंडियन कंपनी को मात्र 50 लाख रुपये में ही 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हस्तांतरित कर दी। ठाकुर ने सवाल उठाया कि क्या कोई राजनीतिक दल इस तरह कर्ज दे सकता है और अगर कर्ज दिया गया



तो क्या उस पर ब्याज लिया गया? ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड, जो

पहले एक दैनिक अखबार था, अब नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता। फिर भी, कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों इसे भारी मात्रा में विज्ञापन दे रही हैं। उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े दैनिक अखबारों को कम राशि मिलती है, जबकि नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। उन्होंने पूछा, क्या यह अखबार कांग्रेस का एटीएम बन गया है? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का हवाला देते हुए ठाकुर ने कहा कि

इसमें अपराध की तारीख, समय, स्थान और लेनदेन से जुड़े तथ्य दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्य जनता के टैक्स के पैसे से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के रूप में धन दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में अखबार को सॉफ्टवेयर दरों पर दी गई अरबों रुपये की संपत्तियों का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इनका कारिया उचित रूप से लिया जा रहा है या यह भी फर्जी है? ठाकुर ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया।

मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश की टिप्पणी पर भारत ने दिया ये जवाब दिखावा करने की बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करने पर दे ध्यान

एजेंसी **नई दिल्ली।** भारत ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में बांग्लादेश के बयान को दृढ़ता से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने ढाका की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया और इसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उपीड़न के बारे में भारत की चिंताओं के साथ समानता स्थापित करने का एक 'छिपा हुआ और कपटपूर्ण' प्रयास करार दिया। बांग्लादेश ने भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में हिंसा के बीच अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल



ने एक बयान में कहा, 'हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं।' बयान में कहा गया, 'यह बांग्लादेश में

अल्पसंख्यकों के लगातार उपीड़न पर भारत की चिंताओं के साथ तुलना करने का एक छिपा हुआ और कपटपूर्ण प्रयास है, जहां ऐसे कृत्यों के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अनुचित टिप्पणी करने के बजाय, बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह के अंत में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद के सुरी, धुलियान, समसेरगंज और जंगीपुर इलाकों में हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और

सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद केंद्रीय बलों की तैनाती की गई और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा था, हम मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश को शामिल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से खंडन करते हैं। हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने की अपील करते हैं।

ब्रिटेन को उप्र. और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने का न्योता

एजेंसी **नई दिल्ली।** रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दो दिवसीय लंदनयात्रा के दौरान वार्ताओं के माध्यम से ब्रिटेन के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को पहले से सशक्त बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई। यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटेन के साथ वार्षिक द्विपक्षीय रक्षा वार्ता के लिए उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रक्षा सचिव 16-17 अप्रैल तक लंदन की दो दिवसीय यात्रा पर थे। रक्षा सचिव ने लंदन में रक्षा मामलों के स्थायी उपसचिव डेविड विलियम्स



दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और रक्षा संबंधों को पहले से सशक्त बनाने के लिए दोनों

देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने ब्रिटेन की कंपनियों को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भारत के विशेष रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय रक्षा सचिव ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन

पॉवेल के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहभागिता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजेश कुमार सिंह ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित भारत-ब्रिटेन रक्षा उद्योग गोलेमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों की संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नौसेना प्रणालियों, ड्रोन, निगमनी, रक्षा अंतरिक्ष और विमानन जैसे प्रमुख रक्षा क्षेत्रों में भारतीय स्टार्ट-अप की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख किया।

थल सेना प्रमुख ने यादव से की सौजन्य भेंट



एजेंसी **भोपाल।** मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से आज थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समल भवन में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्रम और राजा भोज की

मूर्ति भेंट कर थल सेना प्रमुख श्री द्विवेदी का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री डॉ यादव को मण्णपुरी शैली में निर्मित राधा कृष्ण की प्रतिकृति भेंट की। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह तथा मेजर जनरल सुमित भी उनके साथ उपस्थित रहे।

सविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, लोकतंत्र के चारों स्तंभों का सम्मान जरूरी :प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने समाचार एजेंसी खास बातचीत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर केंद्र सरकार से जवाब तलब करने, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर विपक्ष का पक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सर्वोच्च हैं। मैं उनकी बातों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि भारत का संविधान स्पष्ट है। लोकतंत्र चार स्तंभ पर टिका है- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हर स्तंभ के पास अपने-अपने अधिकार हैं और उनका हनन नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 और 145 पर न्यायालयों ने समय-समय पर अलग-अलग राय दी है और उन सभी का सम्मान है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने और केंद्र सरकार से जवाब मांगे जाने के फैसले का तिवारी ने समर्थन दिया।

दिल्ली में अवैध ढाबों पर मनजिंदर सिंह सिरसा का सख्त एवशन, तुरंत सील करने के लिए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पास रघुवीर नगर इलाके का दौरा किया। वहां, उन्होंने सड़कों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने अधिकारियों को अवैध ढाबों और कोयले के तंदूरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। इस मौके पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने समाचार एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए कहा कि अवैध ढाबे, पार्किंग और प्रतिबंधित कोयले के तंदूर, जो प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें हटाने का अधिकारियों को आदेश दिया है। आज ही इन्हें सील किया जाए और उनके मोटर काटे जाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित और खुबसूरत दिल्ली बनाना है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के अंदर बाहर से प्रवेश करने वाले 10 से 15 साल पुराने किसी भी वाहन को प्रवेश करते ही एक संदेश मिलेगा, जिसमें चेतावनी दी जाएगी कि उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। हम वाहनों को पहले से संदेश भेजकर सलाह देंगे कि वे ऐसे वाहन दिल्ली में न लाएं। हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, जो जियोटेग होंगे। लाउडस्पीकर को लेकर पृष्ठे गए सवाल के जवाब में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि लाउडस्पीकर के संबंध में सभी धर्मों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह धर्म की राजनीति नहीं है। सभी धर्मों को सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दिशा-निर्देश मानने होंगे।

नाबालिग लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के जे-ब्लॉक में 17 वर्षीय एक लड़के की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान उसी इलाके के निवासी राजवीर के बेटे कुणाल के रूप में हुई है। नाबालिग लड़के पर करीब 7-38 बजे हमला हुआ था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चाकू घोंपने की घटना की सूचना सीलमपुर थाने को मिली थी। इसके बाद कुणाल को तुरंत इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद, गहन जांच के लिए क्राइम टीम को मौके पर भेजा गया। सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमों तैनात की हैं। वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और संभावित गवाहों से पूछताछ कर रही है।

विपक्ष के नेताओं पर रेड पड़ना सामान्य सी बात, हैरान होने की जरूरत नहीं : सोमनाथ भारती

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और पेशे से वकील सोमनाथ भारती ने 'आप' नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की छापेमारी को आम सी बात करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर रेड पड़ना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बात करते हुए अंग्रेजी के मशहूर वाक्यांशों को कोट किया। बोले, जब एक कुत्ता इसनाम को काटते तो खबर नहीं है, और जब एक इसनाम कुत्ते को काटते तो यह खबर है। इसी तरह बीजेपी शासन काल में विपक्षी नेताओं पर रेड पड़ना खबर नहीं है। लेकिन, अगर भाजपा के नेताओं पर रेड पड़े तो खबर जरूर होगी। हां, जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ये एजेंसियां रेड करना बंद कर दें, तो खबर जरूर बनेगी। यह तो सामान्य है। यह एजेंसियां उनके हथियार हैं। यह रोज की बात है। इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर नकारात्मक माहौल है।

दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले दो दिन गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत

एजेंसी नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3-4 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती स्थितियां बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की उम्मीद है। राजस्थान में 19 अप्रैल से हीटवेव खत्म होने जा रही है।मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सतह पर तेज हवाएं चलेंगी जिनकी रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चल सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली भी आंशिक रूप से बादल ढांक रहेगे। बहुत हल्की बारिश एवं बूंदबांदी के साथ गरज, धूल भरी आंधी के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। यह हवाएं बढ़कर 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सतह पर स्थायी हवाएं 15-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराई सरकार, डराने के लिए सीबीआई को भेजा: दुर्गेश पाठक

एजेंसी नई दिल्ली। नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के गुजरात सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने केंद्र सरकार पर गुजरात में 'आप' की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उभर कर घर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी कराने का आरोप लगाया, 'ताकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया जा सके'। दुर्गेश पाठक ने बताया कि गुजरात सुबह सीबीआई की एक टीम उनके घर पहुंची और करीब तीन-चार घंटे तक खानबोल करती रही। उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने मेरे बेड, अलमारी और हर कोने को



अप्रैल, के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सतह पर तेज हवाएं चलेंगी जिनकी रफ्तार 20-30 किलोमीटर

वक्फ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत

एजेंसी नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि वैचारिक हमला है। केंद्र सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन एवं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहां आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

सिंघवी ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का अभ्यास, निर्वहन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।

विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगा केंद्र : प्रधानमंत्री

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि दिल्ली वालों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और जीवन की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, कल यमुना की सफाई और पुनरुद्धार के साथ-साथ दिल्ली में पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान पर एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि दिल्ली के मेरे भाइयों और बहनों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और 'जीवन की सुगमता' सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री ने यमुना नदी की मौजूदा स्थिति का आकलन, इसकी सफाई और कायमकरी के लिए चल रही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में

वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं का संचालन व प्रबंधन कर सकता है और उनके चुनावों में नामित हो



सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पांच खंडपीठों के पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक वर्ग की संस्थाओं की स्वायत्तता को इस हद तक कम करना कि वह समाप्त हो जाए, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 11 में चुनावित श्रेणी को हटाकर शत-

प्रतिशत नामांकन का प्रावधान स्वायत्तता के सिद्धांत के विरुद्ध है वक्फ संशोधन अधिनियम के

प्रावधान 9 और 14 पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रावधान 9 कहता है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 12 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं। प्रावधान 14 कहता है कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से सात गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने

गृहमंत्री अमित शाह, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नदी को साफ करने के लिए एजेंसी-वार कार्य योजना की समीक्षा की गई। कार्य



योजना में अल्पकालिक गतिविधियां (3 महीने), मध्यम अवधि की गतिविधियां (3 महीने से 1.5 वर्ष) और दीर्घकालिक गतिविधियां (1.5 से 3 वर्ष) शामिल थीं। नाली प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, सेटेंज और ड्रेजरी

अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान और निगरानी उपायों, यमुना नदी में प्रवाह में सुधार, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, हरित नदी तट विकास और

सर्वजनिक आउटररीज के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर विशिष्ट समयसीमा के साथ चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बंगाल हिंसा को बताया 'शर्मनाक', ममता बनर्जी की भूमिका पर उठाए सवाल

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा को 'शर्मनाक' और इसे सीएम ममता बनर्जी के कामकाज पर लाना धब्बा बताया। बातचीत में सीएम गुप्ता ने कहा, 'जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच दरार पैदा करने में लगी हैं, वह निंदनीय है।' पश्चिम बंगाल में अस्थिर स्थिति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'बहुत शर्मनाक है, अगर राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद

मुख्यमंत्री शामिल होकर जनता को बांटने का काम कर रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा का खामियाजा भुगतने वाले हिंदू परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा, 'जो हिंदू परिवार हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार और इतनी दर्दनाक स्थिति है कि लोगों को वहां से जाना पड़े तो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।' सीएम रेखा गुप्ता की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में स्थिति की

समीक्षा के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। सीएम गुप्ता ने अपने पूर्ववर्ती और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई मुद्दों को लेकर दोहरा खेया अपनाते का आरोप लगाया और उन्हें अवसरवादी करार दिया। मुख्यमंत्री बोलीं, 'वह अवसरवाद की राजनीति में माहिर हैं। वह केवल उन्हीं मुद्दों पर बयान देते हैं, जो उनके अनुकूल हों।' उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने बच्चों के नाम की कसम खाते हैं और फिर से पलत कामों में लिस हो जाते हैं और दार्गी लोगों से हाथ मिला लेते हैं। मुख्यमंत्री ने

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशी धरे गए

एजेंसी नई दिल्ली । दक्षिण पश्चिमी जिले की साउथ कैम्पस पुलिस ने इलाके में अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश करने के बाद उन्हें निर्वासन केंद्र भेज दिया है। इनको बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान राबिउल इस्लाम, पत्नी सीमा, बैटा अब्राहम, पापिया खातून, सादिया सुल्ताना, सुहासिनी, आर्यन व रिफत अरा मोयना नामक बांग्लादेशियों के रूप में हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य स्थितियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल को साउथ कैम्पस पुलिस को सत्या निकेतन इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर आरोपित राबिउल इस्लाम को

पकड़ा। पूछताछ में इससे पता चला कि वह साल 2012 में त्रिपुरा बॉर्डर से होकर अवैध रूप से भारत आया। तभी से वह दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रह रहा था। साल 2016 में सीमा नामक लड़की से शादी करने के बाद पत्नी सीमा व बाद में बेटे अब्राहम के साथ यहां बस गया। वह दिल्ली में साफ सफाई व घरेलू सहायक का काम करता था। इसकी पत्नी भी घरेलू सहायिका थी। जांच में इसके पास से आधार कार्ड भी बरामद हुआ। उसने पुलिस को बताया कि उसके कुछ रिश्तेदार दिल्ली के कटवारिया सराय व मोती बाग इलाके में पहले से रह रहे थे। वह काम व अन्य बहाने से अवसर वहां आया करता था। इसके बाद आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने पांच अन्य आरोपितों को जिले के विभिन्न इलाकों से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशियों में शामिल पापिया खातून को उसके बांग्लादेशी पति ने छोड़ दिया। इसके बाद साल 2007 में वह घोजा डोंगा बॉर्डर से होते हुए अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर गई।

केजरीवाल की राजनीति अब घोटालों और फरेब की पहचान बन चुकी है: चुध

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुध ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलेते हुए कहा कि अब सारा देश देख रहा है कि स्वयंभू ईमानदार केजरीवाल ही इस देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी पूरी पार्टी एक संगठित घोटालों का गिरोह बन गई है। चुध ने कहा कि दुर्गेश पाठक के आवास पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी कोई साधारण कार्रवाई नहीं बल्कि केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही भ्रष्टाचार की साजिश का पर्दाफाश है। यह वही दुर्गेश पाठक हैं, जो गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और दिल्ली के शराब घोटाले से निकाले गए अवैध धन को 'चंद्र' बनाकर गोवा चुनाव में पानी की तरह बहाया। अरविंद केजरीवाल उस गिरोह के सरगना हैं, जिन्होंने ईमानदारी का झूठा चोला पहनकर देश को ठगने का

काम किया है। आम आदमी पार्टी अब आम नहीं, बल्कि अपराधियों की पार्टी बन गई है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में तरुण चुध ने कहा कि वर्ष



2016 में कनाडा में आयोजित एक संदिग्ध धन संग्रह कार्यक्रम और उसमें शामिल विदेशी नागरिकों के नाम पर किया गया फर्जी लेनदेन वह साबित करता है कि यह केवल चुनावी धांधली नहीं बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था पर सुनियोजित हमला था। एक ही मोबाइल

एसआरसीसी में तीन दिवसीय क्रॉसरोड्स उत्सव का समापन

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉमर्स कॉलेज (एसआरसीसी) के छत्र संघ ने क्रॉसरोड्स उत्सव का आयोजन किया, जिसका समापन था। तीन दिवसीय इस उत्सव में छात्रों का उत्साह दिखाई दिया। यह उत्सव छात्रों के लिए बेहद उत्साहवर्धक रहा। इसमें कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ अन्य महाविद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया। इस उत्सव के दूसरे दिन छात्रों में ऐसा उत्साह था कि कड़कती धूप में दिन के बारह बजे वह मौत का कुआं देखने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहे जिसमें कई बच्चों के धूप के कारण तबियत भी बिगड़ गई। श्याम और यश ने बताया कि कैसे बच्चे दो घंटे लाइनों में लगे रहे बिना ये सोचे कि तबियत खराब हो जाएगी। लंबी लाइन और धूप के वजह से दो बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो गई। उल्लेखनीय है कि क्रॉसरोड्स दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे बड़े और बहुमूर्तिधित वार्षिक कॉलेज सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। वर्ष 1976 में शुरू हुए इस उत्सव ने हर गुजरते संस्करण के साथ नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। यह अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है।

प्लेसमेंट 2024-25: आईआईटी दिल्ली के यूजी छात्रों को अब तक 850 अनूटे ऑफर मिले, पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के स्नातक (यूजी) छात्रों को अब तक करीब 850 जॉब ऑफर मिले हैं। चालू वर्ष में ऑफर की संख्या पिछले तीन वर्षों में मिले ऑफर से अधिक है। वर्ष 2022 में 712, 2023 में 768 और 2024 में 781 ऑफर मिले थे। प्लेसमेंट सीजन अभी भी जारी रहने के कारण ऑफर में और वृद्धि होने की उम्मीद है।आईआईटी के एक बयान में कहा कि इस वर्ष अब तक कैम्पस में यूजी छात्रों को दोहरे अंकों में ऑफर देने वाले भर्तीकर्ताओं में अमेरिकन एक्सप्रेस, बार्कलेज, बीसीजी, ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुगल, ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल, मोशो, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, पेयू, स्क्वायरस्पॉट कैपिटल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी

लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएफयू) ने भी इस प्लेसमेंट सत्र में आईआईटी दिल्ली के यूजी छात्रों



को नियुक्त किया। यूजी छात्रों को जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका सहित कई वैश्विक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संगठनों से 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।संस्थान द्वारा किए गए एक एगजिट सर्वे के अनुसार, 2024 में स्नातक करने वाले लगभग 30 प्रतिशत छात्रों ने विविध करियर विकल्प चुने (स्व-रोजगार/स्टार्ट-अप/उद्यमिता 7 प्रतिशत, उच्च

को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा, 'गुजरात में जब 'आप' ने पांच विधायक जिला और 41 लाख से ज्यादा वोट मिले, तभी से केंद्र सरकार हमारी पार्टी को डराने और खत्म करने की कोशिश कर रही है।' दुर्गेश पाठक ने कहा कि वह एक

जिम्मेदार नागरिक हैं और किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, 'मुझे डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। जो भी जानकारी मांगी जाएगी, मैं दूंगा और जांच में पूरा सहयोग करूंगा।'

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का यह तरीका है - विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, उनके संसाधन खत्म करना और कार्यकर्ताओं को तोड़ना। उन्होंने कहा, 'अगर विपक्ष को खत्म करने की यह योजना है तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।'

संपादक की कलम से संशोधित वक्फ अधिनियम को लागू करना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती

संशोधन वक्फ न्यायाधिकरण को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें विलंब के लिए 'पयाप्ट कारण' नहीं बताया गया है। यह विस्तार के लिए अधिकतम समय भी निर्धारित करता है तथा अनुरोध करने के लिए चरणों की रूपरेखा भी बताता है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इस कानून का हड़तापूर्वक बचाव किया।

वक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम-2025 को लेकर काफी चिंता है, जिसे गत बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया था। यह विवादास्पद विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को आधुनन करता है और केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण देता है। अगले दिन राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले हफ्ते इसे स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार यह विधेयक अब कानून में तब्दील हो गया है।

वक्फ इस्लाम के उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का समर्पण है और इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें मस्जिदें, मदरसे, आश्रय गृह और मुसलमानों द्वारा दान की गयी हजारों एकड़ जमीन शामिल हैं। इनका प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है, तथा कुछ को अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (उमीद) पारदर्शिता, जवाबदेही, आधुनिकीकरण तथा दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करता है। इसमें गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं तथा वित्तीय सुधार के प्रावधान शामिल हैं। इन परिवर्तनों में अतिक्रमण को रोकना तथा संसाधनों का उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए सुनिश्चित करना शामिल है।

संशोधन वक्फ न्यायाधिकरण को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें विलंब के लिए 'पयाप्ट कारण' नहीं बताया गया है। यह विस्तार के लिए अधिकतम समय भी निर्धारित करता है तथा अनुरोध करने के लिए चरणों की रूपरेखा भी बताता है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इस कानून का हड़तापूर्वक बचाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, 'संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देगा तथा लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करेगा,' उन्होंने सोशल मीडिया एक्स में लिखा। सरकार का कहना है कि 1995 के कानून में वक्फ संपत्तियों, शीर्षक विवादों तथा वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को विनियमित करने के संबंध में कुछ खामियां हैं। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'अगर सरकार यह विधेयक नहीं लाती है, तो संसद भवन और हजारों अड्डे को वक्फ संपत्ति माना जायेगा।' यह संदर्भ हमें उन विशिष्ट मुद्दों को समझने में मदद करता है, जिन्हें संशोधन संबोधित करने का लक्ष्य रखता है।

इस सप्ताह संसद में लगभग 12 घंटे तक चली बहस के दौरान विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निचले सदन में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न दलों के विरोध के बावजूद, यह विधेयक मोदी सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लाया गया।' विचारों की यह विविधता इस मुद्दे की जटिलता और महत्व को दर्शाती है।

कांग्रेस सदस्य इमरान मसूद ने सरकार से पूछा कि वह 'अभ्यास करने वाले मुसलमान' को कैसे परिभाषित करेगा। उन्होंने पूछा, 'आपकी परिभाषा क्या है? सभी मुसलमान पांच बार नमाज नहीं पढ़ते हैं, और सभी मुसलमान रोजा नहीं रखते हैं। मानदंड क्या होंगे?' मुस्लिम समूहों ने तर्क दिया है कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना है। उनका मानना ​​है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के सवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। उन्होंने बढ़ते सरकारी नियंत्रण और व्यापक परामर्श की कमी का भी विरोध किया। ये चिंताएं मुस्लिम समुदाय पर विधेयक के संभावित नकारात्मक प्रभाव और आगे की चर्चा और परामर्श की आवश्यकता को उजागर करती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का मानना ​​है कि यह सरकार को बहुत अधिक शक्ति देता है और वर्तमान कानून में कई बदलावों का सुझाव देता है। लोकसभा में बोलते हुए, कांग्रेस नेता गौरव मोदी ने कहा कि यह विधेयक 'संविधान को कमजोर करेगा, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करेगा, भारतीय समाज को विभाजित करेगा और अल्पसंख्यकों को वंचित करेगा।' केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि विश्व अल्पसंख्यकों को डरा रहा है और 'यह भ्रम पैदा कर रहा है कि यह विधेयक मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों और उनकी दान की गयी संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।'

सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनायेगा।

इस विधेयक को पहली बार पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था। कड़े विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें समिति द्वारा सुझाये गये 25

गर्मियों में धूप में ज्यादा देर रहते हैं तो न करें ये गलतियां, बिगड़ सकती है सेहत

गर्मी बढ़ती जा रही है. ऐसे में उन लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं जिन लोगों की फील्ड जॉब है या फिर जिन्हें किसी और कारण से ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है. ऐसे लोगों को अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए. क्योंकि यदि आप धूप में ज्यादा देर तक रहते हैं तो इसका गंभीर प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है. ज्यादा देर धूप में रहने से डिहाइड्रेशन हो सकता है बल्कि नौबत अस्पताल में भर्ती होने तक भी आ सकती है. हीट स्ट्रोक का भी खराब रहता है. हीट स्ट्रोक होने पर यदि कुछ ही देर में उपचार नहीं मिलता है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है.

ज्यादा देर तक धूप में रहने वाले लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे वह तेज धूप से होने वाले गंभीर नुकसान से बच सकें. सिर पर पड़ने वाली तेज घूप के कारण कुछ ही देर में आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है. तेज धूप में मति भ्रम और देखने की क्षमता भी प्रभावित होती है. तेज धूप के कारण सनबर्न का खतरा भी रहता है. इसके अलावा सबसे गंभीर खतरा हीट स्ट्रोक का रहता है. हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है. हीट स्ट्रोक से मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसलिए ज्यादा देर धूप में रहना पड़े तो कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए.

यह सावधानियां बरतें

यदि आप ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो खुद को हाइड्रेट जरूर रखें. नींबू की बिना सोडे वाली शिकंजी आपको ज्यादा देर तक हाइड्रेट रहने में ज्यादा मदद कर सकती है. इसके साथ ही ज्यादा देर धूप में रहना पड़ता है तो सिर को ढक कर रखें. सिर पर तेज धूप पड़ने से माइंड के टिश्यू को भी नुकसान पहुंचता है. हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर को गर्मी से बचाया जा सके.

यह काम भूलकर भी न करें

तेज घूप से से ऑफिस या घर पहुंचने पर तुरंत ठंडा पानी पीने से बचें. ज्यादा देर धूप में रहने के बाद तुरंत नहाने से भी बचें, इससे शरीर का तापमान बिगड़ सकता है और आप लू की चोट में भी आ सकते हैं. तेज धूप से आने के पर पहले शरीर के तापमान को सामान्य होने दें उसके बाद एसी चालू करें।

-ललित गर्ग-

न्यायपालिका पर जनता का भरोसा लोकतंत्र का अहम आधार है। न्यायिक प्रणाली में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्षता की जरूरत है, इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतों तक के न्यायाधीशों को संपत्ति सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाए जाने की अपेक्षा आजादी के अमृतकाल में तीव्रता से की जा रही थी, ताकि न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले संदेह दूर हो सकें, यह मुद्दा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर जली हुई नोटों की गड्ढी मिलने जैसी घटनाओं और उनसे उपजे विवादों के बाद गंभीर सार्वजनिक विमर्श का बन गया था। जनचर्चाओं एवं आदर्श राष्ट्र-निर्माण की अपेक्षाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने पर जो सहमति जताई है, वह सही दिशा में उठाया गया उचित एवं प्रासंगिक कदम है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का उस पर भरोसा मजबूत होगा। देश में न्यायालयों को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है, जो आम लोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद है। न्याय करने वाले न्यायाधीशों पर संदेह के बादल मंडराना न्याय-प्रक्रिया पर भरोसा कम करने का एक बड़ा कारण बनता रहा है। अब जनता की अपने पंच-परमेश्वरों की स्वच्छ-धवल छवि की आकांक्षा पूरी होते हुए दिखाई देना एक रोशनी बना है, जिससे न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास ज्यादा मजबूत होगा। नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी ही चाहिए। न्यायधीशों को भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार हर न्यायाधीश को अपनी प्रॉपर्टी और देनदारियों के बारे में चीफ जस्टिस को बताना होता है। बाद में, एक और प्रस्ताव आया कि

अमृतकाल में आभासी करोड़पति

- सर्वमित्रा सुरजन

गरीबी अभिशाप है, यह वाक्य कहने के लिए ठीक है, मगर हकीकत है कि गरीबी मानवनिर्मित त्रासदी है। इसानी सभ्यता के शुरूआती दौर में सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट यानी सर्वाधिक योग्य रहेगा, वो बचेगा, पनपेगा, ऐसी धारणा मानी जा सकती थी, भारत की आदि संस्कृति में इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है कि -‘दैवो दुर्बलघातकः’ यानी भगवान भी दुर्बल को ही मारते हैं।

मुसीबत थी हमारे ही लिए क्यूं।

ये माना हम लिए लेकिन जिए क्यूं।।

19 वीं सदी में मिर्जा ‘मोहम्मद हादी अजीज लखनवी के लिखे इस शेर को पढ़कर 20वीं सदी में लिखे शकील बदायूनी के अमर गीत को पॉकियां याद आ गई- दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिल्ट्र मदर इंडिया का यह गीत जैसे आज भी करोड़ों भारतीयों की हकीकत ही है। गुलामी के लंबे दौर के बाद हम आजाद हो गए, और अब तो आजादी के अमृत महोत्सव को मनाकर आगे भी निकल चुके हैं, लेकिन जीवन के प्याले में जहर खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है।गरीबी अभिशाप है, यह वाक्य कहने के लिए ठीक है, मगर हकीकत है कि गरीबी मानवनिर्मित त्रासदी है। इसानी सभ्यता के शुरूआती दौर में सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट यानी जो सर्वाधिक योग्य रहेगा, वो बचेगा, पनपेगा, ऐसी धारणा मानी जा सकती थी, भारत की आदि संस्कृति में इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है कि -‘दैवो दुर्बलघातकः’ यानी भगवान भी दुर्बल को ही मारते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसी बातें कतई स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। खासकर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां आजादी के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें राज्य पर लोककल्याणकारी होने की जिम्मेदारी तय की गई। अगर इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाए तो फिर न किस्मत को दोष देने की नौबत आएगी, न गरीबी को पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम समझकर उसे अभिशाप कहा जाएगा। आज भारत में अगर 80 करोड़ लोग गरीबी के कारण पांच किलो अनाज लेने पर मजबूर हैं तो यह सवाल सरकार से बनता है कि आखिर पांच सालों से चल रही इस योजना को और कितने साल चलाया जाएगा। कब हालात ऐसे बनेंगे कि हर हाथ को काम होगा ताकि आत्मसम्मान के साथ अपने भोजन-पानी का इंतजाम नागरिक खुद करें। अफसोस की बात है इसे बुनियादी सवाल पर लगभग शून्य चर्चा होती है। अगर कहीं सवाल उठे तो मोदी महामांव हैं, अवतारी हैं, ऐसे कसीदे गढ़कर उन जवाबों को खारिज किया जाता है। हाल ही में भाजपा सांसद कंगना रावत ने नरेन्द्र मोदी को अवतारी कहा है और ये अकेला या पहला उदाहरण नहीं है। जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें प्रातःस्मरणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हालांकि ऐसी प्रशस्तियों से कोई ईंसान वाकई भगवान का अवतार नहीं बन जाता, नरेन्द्र मोदी ईंसान हैं और वहीं रहेंगे। और ईंसान नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री की कुसी पर जब बैठे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनसे ही सवाल किए जाएंगे कि अगर उनके शासन में लोगों को किसी भी किस्म का कष्ट है तो उन्हें दूर करने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं। मगर ऐसे सवाल करने की जगह हिंदू-मुस्लिम विमर्शों में वक्त जाना किया जा रहा है, या फिर ऐसी खबरे प्रसारित-प्रचारित हो रही हैं, जिनका जनसामान्य से कोई लेना-देना नहीं है। अभी पिछले साल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के पहले के भव्य जलसे और बाद में शादी की धूमधाम कितने वक्त तक मीडिया में छाई रहीं ये पाठकों को याद होगा। फिर उन्हीं अनंत अंबानी के निजी जंगल वनतारा पर ऐसी खबरे बनने लगीं, हालांकि यहां भी जो सवाल उठाया जाना चाहिए था।



न्यायाधीश चाहें तो अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं, स्वेच्छिक था। पिछले लगभग तीन दशक में, यह मामला कई बार उठा है। सूचना का अधिकार लागू होने के बाद यह बहस भी हुई कि न्यायपालिका इसके दायरे में क्यों नहीं? इसके पीछे यही तर्क रहा कि किसी निजी जानकारी को तब तक साझा करने की जरूरत नहीं, जब तक उससे सार्वजनिक हित न जुड़े हों। 2010 और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब इसी तथ्य को आधार बनाकर कहा गया कि जानकारी सार्वजनिक करना न्यायधीशों की इच्छा पर है। एक तरह से यह व्यवस्था न्यायाधीशों को लगातार संदेहों के घेरे में रखती रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता कायम करने वाला एक सराहनीय कदम होगा। जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग के पीछे बड़ा तर्क भी यही दिया जाता रहा है कि जब तक जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं

होगी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठोस कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज, सरल पारदर्शी एवं समानतामूलक होने के साथ आम आदमी के भरोसे वाली होनी चाहिए। इसके लिये भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीयकरण के लिये ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही आवश्यक मूल्य है। सरकार को एक संसदीय समिति ने 2023 में सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य की जाए। हालांकि कठिनता कारणों से सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ी। इसका एक बड़ा कारण सरकार पर यह आरोप लगना भी बना कि सरकार न्यायपालिका में अनावश्यक राजनीतिक दखल दे रही है। लेकिन न्यायपालिका की साथ के लिए उसका स्वतंत्र होना और दिखना भी जरूरी है। लेकिन समप्ति की घोषणा के मामले में उन्हें अतिरिक्त सुविधा देना या उनके लिये अतिरिक्त सुविधा का होना, संदेह का कारण बनता रहा है। दरअसल, वर्तमान परिपाटी के

टैरिफ वॉर ठहरा है, स्थगित नहीं हुआ



साथ साथ भी खो रहा है।

चाहे यह फैसला कुछ दिनों के लिये आगे बढ़ा हो पर ट्रम्प इसे लेकर जिस कदर उत्साहित हैं उससे लगता नहीं कि वे यह कदम वापस लेंगे। अपने पाटी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि 'इस ऐलान के बाद अमेरिका में इतना पैसा आ रहा है जितना पहले कभी नहीं देखा गया।' वास्तविकता तो यह है कि अभी इस फैसले पर ठीक से अमल शुरू भी नहीं हुआ है पर अमेरिकी नागरिकों में चिंता है कि बहुत सी वस्तुएं उन्हें महंगी मिलेंगी, खासकर जिनके लिये अमेरिका पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने निलंज्जतापूर्वक एक ऐसी गर्वीक की जो कि शर्मनाक व असंसदीय है; जिसे न उद्धृत किया जा सकता है और न ही अभिव्यक्त। अमेरिकी शब्दावली में कहे गये उनके बयान का आशय यह था कि दुनिया एक तरह से उनके कदमों में आ गयी है। 90 दिन टलने के कारण जो उछाल आया वही बताने के लिये काफी है कि ट्रम्प का टैरिफ वॉर किस कदर से शेरार बाजारों पर कहर बनकर

टूटा है, तभी तो वह कदम, चाहे कुछ ही दिनों के लिये टालते ही शेरार बाजारों की सांसें लौट आया। खुद अमेरिकी बाजारों का झूम उठना बताता है कि राष्ट्रपति का यह फैसला अमेरिकी निवेशक भी नहीं झेल पायेगे। इसके साथ यह भी साफ हो गया है कि 1991 में अमेरिका प्रवर्तित वैश्विक अर्थव्यवस्था की ट्रम्प रती भर परवाह नहीं करते। वैसे ही 'अमेरिकी फर्स्ट' के नारे पर जीतकर दूसरी बार जीतने वाले ट्रम्प के इस कदम से 3 माह दुनिया का व्यवसाय ऊहापोह में रहेगा। अलाबामा, ट्रम्प के खासमखास मरक को इस उछाल से बड़ा लाभ मिलने की सूचना है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रम्प बता रहे हैं कि उनके इस कदम से उनके कुछ मित्रों को कितना लाभ मिला है। वैसे जिस चीन को सबक सिखाने के नाम पर ट्रम्प ने इतना बड़ा प्रपंच रचा और सारी दुनिया को लोपटे में लिया है, वह चीन बिलकुल निश्चित है। अपने कुल उत्पादन का लगभग 70 फीसदी वह निर्यात करता है- वह भी अपनी जनता की जरूरतें पूरी करने के बाद। चीन अमेरिकी वस्तुओं पर उतना निर्भर नहीं जितना कि अमेरिका चीन पर। उसे यदि अमेरिकी बाजार महंगे लगेंगे तो वह

अपना उत्पादन दूसरे देशों में उतार सकता है। चीन अपने सस्ते उत्पादनों, शानदार लॉजिस्टिक्स और तेज डिलीवरी के चलते किसी भी देश का मुकाबला करता है। बहुत से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश महंगी अमेरिकी वस्तुओं की बजाय सस्ती चीनी सामग्रियों को पसंद कर सकते हैं। ट्रम्प का टैरिफ वॉर बहुत से देशों के लिये विनाशकारी हो सकता है लेकिन चीन का इससे बेपरवाह होना लाजिमी है। बहुत से विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि यह अमेरिकी दांव चीन के लिये वरदान साबित हो सकता है।

विशेषकर, मैनुफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटे-कल पुर्जों से बड़ी मशीनों आदि के लिये उसे नये बाजार मिल सकते हैं। सम्भवतः इससे वह बात साबित हो सकती है कि कोई भी अदूरदर्शितापूर्ण फैसला लेने के जो नुकसान होते हैं वे वापस लेने या कुछ दिन टाल देने से और भी विनाशकारी साबित होते हैं। देखना होगा कि तीन माह बाद जब ट्रम्प-टैरिफ लागू होते हैं तो उसका असर कितना और किन देशों पर पड़ता है। सम्भवतः ज्वादातर देश इससे निपटने की तैयारियां कर लें।

जगह अनिवार्य भी है।

न्यायपालिका ही फरियाद का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बल्कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायाधीश अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें तो इससे जनता को उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा। अब तक का अनुभव बताता है कि उच्च न्यायालयों के स्तर पर भी जजों में संपत्ति को सार्वजनिक करने की प्रवृत्ति काफी कम है। मार्च 2025 तक, उच्च न्यायालयों के कुल 763 में से सिर्फ 49 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अभी इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा करना कानूनन अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में आम जनमानस में धारणा बनी रहती है कि न्यायपालिका के बाबत भी कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रश्न न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही से भी जुड़ा है। यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि विधि एवं न्याय विभाग की संसदीय समिति ने वर्ष 2023 में न्यायाधीशों के लिये अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा की सिफारिश की थी। लेकिन इस बाबत अभी तक कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अब स्वयं न्यायपालिका की तरफ से ऐसी व्यवस्था लागू करने का सराहनीय प्रयास होना सुखद ही कहा जायेगा। न्यायपालिका के प्रति अविश्वास में पारदर्शिता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता व शुचिता की पक्षधर रही है। जनता इस कसौटी पर अपने न्याय के देवताओं को भी खरा उतरता देखना चाहती है। निस्संदेह इस तरह के फैसले का समाज में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से दूरगामी प्रभाव भी होगा। इस दिशा में ऐसी किसी भी पारदर्शी व्यवस्था का समाज में स्वागत ही होगा। ऐसे किसी भी कदम से उस आम आदमी के विश्वास को भी बल मिलेगा जो हर तरह के अन्याय व भ्रष्टाचार से तंग आकर उम्मीद की अंतिम किरण के रूप में न्यायालयों का रख करता है।

अमेरिका में पांच लाख का इनामी खालिस्तान समर्थक आतंकी पासिया गिरफ्तार

एजेंसी वाशिंगटन। अमेरिका में खालिस्तान समर्थक संधिगत आतंकी व गैंगस्टर हेमपी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भारत के चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब में कई हमले करने का आरोप है। उसे इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्मेंट ने कस्टडी में ले लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर भारतीय जांच एजेंसी (एनआई) ने पांच लाख रुपये का इनाम रखा था। गिरफ्तारी रात को की गई। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पासिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वह पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरिवंदर सिंह रिदा के लिए भी काम करता था। इसके निशाने पर पंजाब के जालंधर के एक पूर्व पुलिस अधीक्षक और उनका परिवार था। उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा।

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से की 1971 के अत्याचारों पर सार्वजनिक माफी की मांग

ढाका। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता आयोजित हुई, जिसमें बांग्लादेश ने ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विशेष रूप से, बांग्लादेश ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए औपचारिक और सार्वजनिक माफी की मांग दोहराई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में अब भी मौजूद कई असुलखे मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सबसे अहम 1971 के युद्ध के दौरान हुई घटनाएं रहीं, जिनमें लाखों लोगों को जान गई और हजारों महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ा। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने बैठक के बाद बताया कि पाकिस्तान के साथ स्थायी और सकारात्मक रिश्ते स्थापित करने के लिए पुराने विवादों का समाधान आवश्यक है। उन्होंने 4.32 अरब डॉलर के वित्तीय दावे के साथ-साथ 'फंसे हुए पाकिस्तानियों' की वापसी और 1970 के चक्रवात के दौरान मिली अंतरराष्ट्रीय मदद के वितरण जैसे विषयों को भी उठाया। पाकिस्तान की ओर से विदेश सचिव अमना बलूच ने बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि पाकिस्तान ने फिलहाल इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने की इच्छा जताई है।

पोखरा हवाईअड्डा निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा, संसदीय जांच समिति ने सौपी रिपोर्ट

काठमांडू। चीन से महंगा ऋण लेकर बनाए गए पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये के घोटाला होने का खुलासा संयुक्त संसदीय समिति की जांच में हुआ है। संसद की इस जांच समिति ने 11 बिंदुओं में अनियमितता होने और इससे संबंधित दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। आरपीपी अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन के संयोजकत्व में गठित इस समिति ने जांच रिपोर्ट संसद की लेखा समिति को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 1272 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में भ्रष्टाचार की नीयत से बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया। निर्माण कार्य पूरा होने पर कुल 2600 करोड़ का भुगतान किए जाने का प्रमाण मिला। राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि सिर्फ टेक्स छूट के नाम पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है और महालेखा परीक्षक ने भी रिपोर्ट के माध्यम से इस मामले को सार्वजनिक किया है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान हजारों करोड़ रुपये का गबन किया गया है। लिंगदेन ने कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। जांच समिति के एक सदस्य तथा पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले के अनुसार पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण में अनियमितताएं देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक हैं।

नेपाल में राजशाही के पक्ष में आंदोलित नेताओं की रिहाई के लिए आरपीपी 20 अप्रैल को करेगी प्रदर्शन

काठमांडू। राजशाही के पक्ष में आंदोलित राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) ने अपने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई के लिए काठमांडू में 20 अप्रैल को प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आरपीपी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि इनकी बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए जरूरत हुई तो उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद आरपीपी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि राजशाही के पक्ष में आंदोलन के दौरान उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जिसके विरोध में उनकी पार्टी ने 20 अप्रैल को प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काठमांडू के अधिकांश स्थानों को निषेधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे : बेंजामिन नेतन्याहू

एजेंसी यरूशलम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया कि इजरायल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। उनका यह बयान तेहरान और अमेरिकी प्रशासन के बीच नए परमाणु समझौते पर नए सिरे से बातचीत की खबरों के बीच सामने आया। नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'प्रधानमंत्री ने एक से अधिक बार स्पष्ट किया है- इजरायल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने 'ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अनर्गल प्रत्यक्ष और गुप्त अभियान चलाए हैं' और 'ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान का नेतृत्व किया है।' ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास

आराघी ने पिछले ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव



विटोर्फो से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर मुलाकात की।

नेपाल के 'लिटिल बुद्ध' राम बहादुर बमजन यौन शोषण के मामले में निर्दोष साबित

एजेंसी काठमांडू। नेपाल में लिटिल बुद्ध के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नेता राम बहादुर बमजन को जनकपुर हाई कोर्ट ने बाल यौन शोषण के एक मामले में बरी कर दिया है। जस्टिस खेमराज भट्ट और नरिंश्वर भंडारी की खंडपीठ ने जिला अदालत के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए तर्क दिया कि तय सीमा की समाप्ति के बाद बमजन के खिलाफ मामला दायर किया गया था। लिटिल बुद्ध के नाम से मशहूर बमजन 2005 में भोजन या पानी के बिना ही महिलाओं तक ध्यान में रहने के बाद अंतरराष्ट्रीय सुविधों में आए थे। विदेशी मीडिया खास कर भारत के मीडिया में बमजन के बारे में लगातार खबर आने के बाद तपस्या करते बमजन का दर्शन करने दूर-दूर से लोग नेपाल के उस जंगल में जाने

लगे।वह पिछले कुछ समय से अपने ही आश्रम में रहने वाले बालकों के यौन शोषण और अपने चार शिष्यों के



गायब होने सहित विभिन्न आरोपों की जांच के घेरे में है। उन पर अगस्त, 2016 में सलाही में अपने पड़ारकोट आश्रम में 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे चुप रहने की धमकी देने का आरोप था।

सलाही जिला अदालत से तपस्वी बमजन के खिलाफ दी गई 10 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फैसले में ही त्रुटि है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला 1 फरवरी, 2017 तक दायर किया जाना चाहिए था, जबकि यह माला 5 फरवरी, 2017 को दायर किया गया था। बमजन पर दस बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर उनके एक आश्रम में रहने के दौरान किए गए अपराध प्रारंभिक सजा बाल अधिनियम, 2018 पर आधारित थी, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि इस मामले में बाल अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानूनी समय सीमा पारित होने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी।

साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की फोन पर चर्चा

एजेंसी न्यूयार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान उठे विषय भी शामिल हैं। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर बातचीत की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।' टेस्ला देश में मैन्यूफैक्चरिंग बेस स्थापित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने मार्च में भारत में स्टारलैंक

बंधक छोड़ने व इजरायली सेना की वापसी पर हमारा युद्ध बंद करने को तैयार



एजेंसी गाजा शहर। गाजा में इजरायल द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ हमले की कार्रवाई से फिलीस्तीनी कड़पंथी संगठन हमारा बचेन हो गया है। उसने शर्त रखी है कि गाजा से इजरायली सेना पूरी तह से वापस हो। साथ ही फिलिस्तीनी बंदियों को भी छोड़ा जाए तो बदले में इजरायली बंदियों को भी रिहा कर देंगे। इसके बाद युद्ध भी समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि हमारा के इस नए प्रस्ताव पर इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।हमारा के वरिष्ठ पदाधिकारी खलील अल हैया ने

गुरुवार की रात एक टेलीविजन पर कहा कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से दिया जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है तो पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। हालांकि हमारा ने यह भी साफ किया है कि वह इजरायल की उस मांग को मंजूर नहीं करेंगे, जिसमें हमारा को अपने हथियार डालने होंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों इजरायल द्वारा 45 दिन के अस्थायी संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। इसमें शर्त रखी गई थी कि हमारा को पूरी तह से हथियार डालने होंगे। इसे हमारा ने खारिज दिया था।

पाकिस्तान : अफगान शरणार्थियों का जबरन निर्वासन जारी, 2,239 भेजा गया स्वदेश

एजेंसी इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत 2,239 से ज्यादा अफगानों को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा दिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 31 मार्च की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रही। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए खबर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद ने बताया कि शरणार्थी वापस भेजे जा रहे हैं, वे पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा के अलग-अलग जिलों में रह रहे थे। ट्रांजिट कैंप में पहुंचे लोगों में से 894 अफगान नागरिकों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, जबकि 636 के पास अफगान सिटीजन (एससीसी) कार्ड थे। इसके अलावा 709 अफगानों को पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले

कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से सीधे तोरखम बॉर्डर लाया गया। अफगानिस्तान के उद्योग और व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया। जारी



एक बयान में मंत्री ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के मामले में किसी प्रभावी समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। अफगान सरकारी बख़्त समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने शरणार्थियों की स्वेच्छिक वापसी

की वकालत की और कहा कि इसमें यूएनएचसीआर (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी) के तय किए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि यह प्रक्रिया सुरक्षित और समानजनक तरीके से हो। पाकिस्तान से लौट रहे अफगान लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान पहुंचे कई लोगों ने कहा कि अब उनके पास न तो रहने के लिए कोई घर है और न ही घर बनाने के लिए जमीन। अफगान मीडिया चैनल टोलो के मुताबिक, पाकिस्तान की सरकार गए प्रवासी मोहम्मद नबी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। हमारे पास न घर है, न जमीन। हमारा सारा सामान पीछे छूट गया है। हमारे पास न कोई काम है और न ही किसी ने हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था की है। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत एक ठिकाना है।

प्रधानमंत्री ओली की माओवादी को चेतावनी, कहा-द्वंदकाल के दौरान किए गए अपराधों को माफ नहीं किया जाएगा

एजेंसी काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विपक्षी दल माओवादी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के दशकों तक लंबे सशस्त्र संघर्ष के दौरान तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादी द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को किसी भी बहाने माफ नहीं किया जा सकता है। नेपाल के पूर्व सैनिकों और पुलिस स्रोत के छटे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र संघर्ष के कारण पीड़ित हुए एक-एक नेपाली नागरिक को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। माओवादी विद्रोहियों द्वारा आम नागरिकों और नेपाल के सुरक्षा बलों के साथ किए गए अमानवीय और जघन्य अपराधों को आम माफी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए नेपाल

सरकार ने बार बार अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने प्रतिबद्धता भी व्यक्त की



है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संक्रमणकालीन न्याय संपादन में और कठिनाई देरी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश ने द्वंद काल के पृष्ठ के लिए आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही न्याय

प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने

बहाने के तहत हत्या, हिंसा, धार्मिक अतिवाद या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम गठबंधन सरकार में हैं। हमारे पास एकता और राष्ट्र निर्माण की विरासत है और हम एक संप्रभु, एकीकृत नेपाल को नई पीढ़ी को सौंपेंगे। हम राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं करेंगे या अपनी सीमाओं को कम करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने नेपाल जैसे विविध देश में सामाजिक सद्भाव के महत्व पर प्रकाश डाला और पूर्व सैन्य और पुलिस कमियों से देश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। सरकार इसी मार्ग का नेतृत्व कर रही है और हमें अपने पूर्व सैनिकों और सुरक्षा समुदाय से अदृष्ट समर्थन की आवश्यकता है।

यूक्रेन के प्रति नरम पड़े ट्रम्प, कहा- युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं

एजेंसी वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के यूक्रेन के प्रति नरम बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं हैं। वह जल्द ही यूक्रेन के साथ एक मिशनरल डील (खनिज उत्पादन से संबंधित) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलेनी अमेरिका की यात्रा पर हैं।मेलेनी के साथ वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वह जेलेंस्की को युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन इस बात से भी खुश नहीं हूँ कि उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। साथ ही उन्होंने जल्द ही यूक्रेन के साथ मिनीस्टर्स डील पर हस्ताक्षर करने की बात कही। ट्रम्प ने यह बयान इटली की प्रधानमंत्री के सामने दिया है, इसलिए भी इसे खासा अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध को लेकर जेलेंस्की पर खासे हमलावर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया था। इस दौरान ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच वाक्ययुद्ध तक हो गया था। उसके बाद जेलेंस्की ने ट्रम्प को यूक्रेन आकर रूस द्वारा मचाई गई तबाही को देखने का न्यौता दिया था।



यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के वेयरहाउस पर हमला : रूस ने दी सफाई, कहा- नहीं था निशाना

एजेंसी कोएवा। यूक्रेन की राजधानी कीएव में स्थित भारतीय दवा कंपनी कुसुम हेल्थकेयर के वेयरहाउस पर हुए हमले को लेकर रूस ने सफाई दी है। भारत स्थित रूसी दूतावास ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यूक्रेन के आरोपों को खारिज किया है। यूक्रेन ने दावा किया था कि 12 अप्रैल को रूस ने ड्रोन हमले के जरिए इस भारतीय स्वायत्तित वाले वेयरहाउस को निशाना बनाया, जिससे वहां भंडार आग लग गई।

यह फार्मा वेयरहाउस कुसुम ग्रुप की यूनिट 'सैलैडफार्म' का हिस्सा है, जो यूक्रेन में दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस ने साफ किया है कि उसकी सेनाओं ने किसी भी सिविलियन या विदेशी संपत्ति को निशाना नहीं बनाया। दूतावास के अनुसार, उस दिन की सैन्य कार्रवाई विशेष रूप से यूक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानों पर केंद्रित थी, जिनमें विमान संयंत्र, सैन्य एयरबेस ढांचा, बख्तरबंद वाहन



मरम्मत केंद्र और ड्रोन असेंबली वर्कशॉप शामिल थे। रूसी पक्ष ने यह भी कहा कि संभवतः यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम की कोई भी मिसाइल लक्ष्य चूक गई, और वही आबादी वाले इलाके में गिर गई, जिससे वेयरहाउस में आग लग गई। बयान में यह भी जोड़ा गया कि 'इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं।' यूक्रेन ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है

कि कुसुम ग्रुप ने युद्ध के दौरान यूक्रेनी नागरिकों को मानवीय सहायता दी थी, जो इस हमले का संभावित कारण हो सकता है। भारत की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों व कंपनियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। कुसुम हेल्थकेयर एक जानी-मानी

भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी उपस्थिति यूक्रेन, कजाकिस्तान और भारत सहित कई देशों में है। कंपनी यूक्रेन में औषधीय जबरतों की पूर्ति के लिए लंबे समय से कार्यरत है और वहां की स्वास्थ्य प्रणाली में अहम योगदान दे रही है। इस घटना ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच विदेशी कंपनियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, खासतौर पर उन कंपनियों की जो मानवीय आधार पर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं।

ईरान-यूएस वार्ता से पहले सऊदी रक्षा मंत्री की तेहरान यात्रा, रिश्तों में नया मोड़

एजेंसी तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाली वार्ता से ठीक पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान आधिकारिक यात्रा पर तेहरान पहुंचे। इस महत्वपूर्ण दौर के दौरान उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात की और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअजिज का विशेष संदेश सौंपा। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, खामेनेई ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि, ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान, बहराव के साथ रिश्तों को और रीढ़दार बनाने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया था। यह समझौता वर्षों की दुश्मनी और क्षेत्रीय अस्थिरता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तेहरान यात्रा के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टॉफ मोहम्मद बाधेरी से भी मुलाकात की। बाधेरी ने कहा कि, बीजिंग समझौते के बाद से सऊदी और ईरानी सेनाओं के बीच रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार आया है।

बीजापुर में दो नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

बीजापुर/सुकमा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दो सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से आठ बीयर की बोतलों से बने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), स्विच, बैटरी और एक कुल्हाड़ी बरामद किया गया है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक के अनुसार थाना बासागुड़ा, कोबरा 210 और केरिपु 229 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान के तहत गुट्टूम नेण्ड्रा और तिमपुर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने गुट्टूम नेण्ड्रा के जंगल और तिमपुर से दो नक्सलियों को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान ताती लखमा (38 वर्ष), जो नेंड्रा आरपीसी जनताना सरकार का उपाध्यक्ष है और सोनू उईका (28 वर्ष), जो संघम सदस्य है, के रूप में हुई है। दोनों ही तिमपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार जनताना सरकार उपाध्यक्ष ताती लखमा पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह कई गंभीर वारदातों में शामिल था। जिनमें 22 दिसंबर 2023 को कुशवाहा ट्रेक्लस की बस में आगजनी, 6 फरवरी 2024 को तिमपुर के ग्रामीण मिच्चा हड़मा का अपहरण और हत्या, 6 दिसंबर 2024 को तिमपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हत्या और 2 अप्रैल 2025 को डल्ला के पहाड़ी में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना शामिल है। वहीं, गिरफ्तार सोनू उईका भी 6 फरवरी 2024 को मिच्चा हड़मा के अपहरण और हत्या की घटना में शामिल था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय कर दिया गया है और गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ थाना बासागुड़ा में कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय दौतेवाड़ा के समक्ष पेश किया गया है।

युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं: ट्रम्प

वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के यूक्रेन के प्रति सुर बयान रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार नहीं हैं। वह जल्द ही यूक्रेन के साथ एक मिशनर डील (खनिज उत्पादन से संबंधित) पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम होगी वाल्मीकि धाम की स्थापना



बिनोद कुमार, दिव्य दिल्ली: श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम द्वारा दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी ने जानकारी दी कि अलीपुर रोड स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में 22 अप्रैल को वाल्मीकि धाम की स्थापना की जाएगी। मिडिया से बात करते हुए श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जावेरी ने कहा मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक स्थलों का निर्माण कार्य जारी है, जिनमें बरबरीक धाम, वैष्णो धाम, मानसरोवर मंदिर, गुरुद्वारा और राम मंदिर सहित भविष्य में खाटू श्याम धाम के सहयोग से कुल 36 धामों की स्थापना की योजना है, जो अपने आप में भव्य और अद्वितीय होगा। अलीपुर रोड

पर स्थित खाटू श्याम मंदिर धाम में प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं, वहीं एकादशी के अवसर पर यह संख्या चार लाख से भी अधिक हो जाती है। कार्यक्रम में अपरिस्थित पश्चिम विहार के विधायक करनैल सिंह ने कहा खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में वाल्मिकि धाम की स्थापना हिंदू भाईचारा और सोहार्द को बढ़ावा देने वाला है यह कदम समाज में नई मिशाल पेश करेगा। बता दे की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम में घनश्याम गुप्ता जावेरी, संजीव कुमार मित्तल, रमेश गुप्ता, पवल सिंघल, मधु गोपाल गोयल, अनिल गुप्ता, नवीन गर्ग, कुलदीप गोयल, एस एस अग्रवाल, सत्यभूषण जैन, राजेन्द्र कुमार गर्ग, राजेन्द्र पासाद गोयल, डॉ नरेश गुप्ता, विनय सिंघल, हंशराज रलहान सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

शाहजहांनाबाद डेवलपमेंट कारपोरेशन का पुनर्गठन करे दिल्ली सरकार- सीटीआई

दिव्या दिल्ली : सौंदर्यीकरण के बावजूद ऐतिहासिक चांदनी चौक दुर्दशा का शिकार है लालकिला के सामने से फतेहपुरी तक मुख्य सड़क पर अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजरआ रही है, दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने चांदनी चौक के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है उच्च चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव विष्णु भागवंत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शाहजहांनाबाद डेवलपमेंट कारपोरेशन (SRDC) के जरिए 2021-22 में चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के 4 साल बाद चांदनी चौक अब बदहाली का शिकार है अब यहां की देख-रेख नहीं हो रही है, जगह-जगह गंदगी दिखाई पड़ती है, पट्टी बाजार लग रहा है, बेघरों का जमावड़ा लग



गया है। अतिक्रमण की वजह से चलना मुश्किल हो गया है SRDC का अतापता नहीं है सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस भी सक्रिय नहीं है। यहां लालकिला, जैन मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, फतेहपुरी, जामा मस्जिद, चर्च, थोक बाजार हैं, देश-दुनिया से लोग आते हैं। यहां के ताजा हालात देखकर खराब अनुभव

पर्वटक ले जा रहे हैं। बृजेश गोयल ने बताया कि चांदनी चौक ऐतिहासिक मुगलकालीन बाजार है और पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है हमने उट से गुहार लगाई है कि हाईलेवल कमिटी बनाई जाए, जो चांदनी चौक का दौर करे। इसके साथ ही शाहजहांनाबाद डेवलपमेंट कारपोरेशन का भी पुनर्गठन किया जाए और चांदनी चौक की विरासत को फिर से लौटाने का प्रयास किया जाए।

गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव सदर बाजार में धूमधाम से मनाया

दिव्या दिल्ली : नौवें गुरु तेग बहादुर बहादुर जी का प्रकाश उत्सव सदर बाजार के कुतुब रोड पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष श्री राकेश यादव महासचिव सतपाल सिंह मांगा, कमल कुमार, कार्यकरणीय अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, अध्याध्यक्ष दीपक मित्तल, बरी मार्केट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिंदर



आर्य सहित अनेक व्यापारियों ने बड़ी धूमधाम से मनाया इस

मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल' की विजेता बनकर गर्व से भारत लौटीं अनुराधा गर्ग

दिव्या दिल्ली : 'मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल' जैसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के मंच पर अपने रूप-सौंदर्य का पताका वैश्विक स्तर पर फहराते हुए अंतराष्ट्रीय स्तर का खिताब हासिल कर देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाली मिसेज अनुराधा गर्ग की इस बेमिसाल जीत का राजधानी दिल्ली में जमकर जश्न मनाया गया। अनुराधा गर्ग की कामयाबी का जश्न यहां के द पार्क होटल में मनाया गया और इस अवसर पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। बता दें कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के साथ शक्ति व शालीनता की प्रतिमूर्ति अनुराधा गर्ग ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। बताया जाता है कि 'मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल' जैसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के मंच पर अनुराधा गर्ग ने दमदार उपस्थिति के जरिये अपने आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय नारीत्व की भावना को वैश्विक मंच पर जमकर दर्शाया। कुछ समय पहले जब वह इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट



पर पहुंची थीं, तो उन्हें शुभकामना देने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अनुराधा गर्ग के नाम और तस्वीर से

लैस बैनर और पोस्टर पूरे इलाके में अटे पड़े थे और उनके शुभचिंतक और प्रशंसक 'मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल' जैसे वैश्विक

मंच पर उनकी सफलता की कामना के साथ ईश्वर से दुआ भी कर रहे थे। खास बात यह कि भारत की शीर्ष रूप-

राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम को लिखा पत्र

राज्य सरकार से रोहित वेमुला एक्ट नाम से एक कानून बनाने का आग्रह किया



नई दिल्ली कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर राज्य सरकार से रोहित वेमुला एक्ट नाम से एक कानून बनाने का आग्रह किया है। इस कानून के जरिये यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े। राहुल गांधी ने अपने पत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवनकाल में उनके साथ हुए जातिगत भेदभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर ने जो कुछ झेला, वह शर्मनाक था।

राहुल गांधी ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने दिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है,

जिससे वंचित भी सशक्त बन कर जातिभेद को तोड़ सकते हैं। इसके बावजूद लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्रों की जान ली है। इसलिए सिद्धरमैया से आग्रह किया है कि कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे दलित तबके के रोहित वेमुला ने 2016 में आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस ने 2023 के अपने रायपुर महाधिवेशन में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक विशेष कानून पारित करेगी।

छत्तीसगढ़ में 33 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, शाह ने छिपे हुए नक्सलियों से की आत्मसमर्पण की अपील

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों में विभिन्न ऑपरेशन्स में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 33 कुख्यात नक्सलियों को आधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही, सुकमा की बड़ेसेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह पंचायत पूरी तरह नक्सलमुक्त हो गई है। छिपे हुए नक्सलियों से मेरी अपील है कि मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र हथियार डालें और मुखधारा में शामिल हों।

केंद्र सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल, अरविंद श्रीवास्तव बने राजस्व सचिव

नई दिल्ली वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद श्रीवास्तव को शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा किए गए शीर्ष-स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्रीवास्तव वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुअलनम को व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह मनोज गोविल का स्थान लेंगे। मनोज गोविल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वंदना गुरनानी के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति के स्थान पर की गई है। वंदना गुरनानी कर्नाटक कैडर के 1991 बैच की आईएएस हैं।



बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी राजित पुन्हानी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को संस्कृति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कैडर की 1990 बैच की आईएएस मीता आर. लोचन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की

सचिव नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के मोसेस चालई को वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष श्रीवास्तव को गृह मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय परिषद सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की चाकू घोपकर हत्या, इलाके में तनाव

नई दिल्ली राजधानी के उत्तर पूर्वी जिलान्तर्गत सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम 17 वर्षीय एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। नाबालिग पर हमला उस समय हुआ, जब वो घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। पूरे मामले में एक लड़की के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। इस घटना के बाद इलाके से हिंदुओं के पलायन की बात सामने आ रही है। लोगों ने अपने घरों के बाहर "ये मकान



बिकाऊ है" लिखकर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने उप के मुख्यमंत्री व दिल्ली की मुख्यमंत्री से मदद की बात लिखी है। इस हत्याकांड के विरोध में

शुक्रवार को सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। घटना में मारे गए नाबालिग की पहचान कुनाल के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के

अनुसार उक्त मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपितों की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल, तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस के अनुसार कुनाल परिवार के साथ सीलमपुर स्थित जे ब्लाक में रहता था। परिवार में पिता राजवीर, मां, तीन भाई व एक बहन हैं। पिता आँटो चालक हैं जबकि कुनाल गांधी नगर में एक कपड़े की दुकान में काम करता था।

अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने संभव जैन से किया विवाह

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता का शुक्रवार को उनके कॉलेज मित्र संभव जैन के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। दिल्ली के कपूरथला हाउस में शादी और रिसेप्शन दोनों हुए। कपूरथला हाउस पंजाब के मुख्यमंत्री का दिल्ली में आधिकारिक आवास है। विवाह समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आयी हैं। वीडियो में

अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान समारोह में डांस करते देखे जा सकते हैं। हर्षिता और संभव की मुलाकात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में हुई थी। दोनों यहां एक साथ पढ़ते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कुछ चुने हुए मेहमान इस शादी में शामिल हुए। इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल रहे।